भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व के एक हजार तीन सौ इकतीस स्मारक/स्थल हैं ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन स्मारकों की नियमित रूप से देख-भाल, संरक्षण और परिरक्षा की जाती है । आवश्यकता, उपलब्ध संसाधनों और पुरातत्वीय मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए इनके संरक्षण और परिरक्षण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 201.15 लाख रुपये का आबंटन निर्धारित किया गया है ।

नए विश्वविद्यालय खोले जाने संबंधी लंबित प्रस्ताव

1547. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास मध्य प्रदेश में या देश के अन्य किसी राज्य में एक नए विश्वविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अलग से विश्वविद्यालयों के खोले जाने के बारे में विशेष रूप से पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिये सरकार की क्या नीति है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद अधिनियम और राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधान मंडल अधिनियम द्वारा स्थापित किये जाते हैं । मध्य प्रदेश अथवा अन्य किसी राज्य में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है । क्षेत्र की शैक्षिक और अन्य आवश्यकताओं तथा नये विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शी रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा पिछड़े अथवा आदिवासी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है ।

Environmental clearance to industries in Assam

1548. SHRI BHADRESWAR BURAGOHAIN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what are the details of the industries in Assam which are pending environmental clearance; and

(b) by when they are expected to get clearance from Government?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NILAMANI ROUTRAY): (a) No proposal for environmental clearance for industrial project in Assam is pending with this Ministry.

(b) Does not arise.

Formula for supplying white Printing Paper to States

1549. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the pricing formula for supplying white printing paper to the States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): As per the pricing formula for supplying concessional white printing paper to the States, the price payable to Hindustan Paper Corporation is the lowest listed price amongst five identified and comparable mills, as available on the last day of the preceding quarter with a discount of Rs. 300|- per MT.